



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 7 राँची, शुक्रवार 11 पौष, 1937 (श०)
1 जनवरी, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

23 दिसम्बर, 2015

1. उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1879/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 30.12.2010 एवं पत्रांक-49/गो०, दिनांक 06 जनवरी, 2015
 2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3362, दिनांक-18 अप्रैल, 2013; पत्रांक-5136, दिनांक 14 जून, 2013; संकल्प सं०-2484, दिनांक-18 मार्च, 2015 एवं संकल्प सं०-3928, दिनांक 29 अप्रैल, 2015
 3. श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक-184/2015, दिनांक 14 जुलाई, 2015
-

संख्या- 5/आरोप-1-77/2015 का.- 10891/श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-684/03) के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनबाद के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1879/डी0आर0डी0ए0, दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित हैं। प्रपत्र- 'क' में इनके विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

प्रपत्र-'क' में श्री सिंह के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित हैं:-

आरोप संख्या-1. धनबाद प्रखण्ड के ग्राम खरिकाबाद पंचायत भूली में नरेगा योजना अन्तर्गत बी0सी0सी0एल0 द्वारा पूर्व निर्मित पक्की सड़क पर मिट्टी मुरुम पथ निर्माण का प्रस्ताव आपके द्वारा दिया गया। उक्त योजना में सड़क के 230 फीट लंबाई ग्रेड-I एवं ग्रेड- II का कार्य किया गया परन्तु कार्य पूरा नहीं किया गया केवल मुरुम बिछाकर छोड़ दिया गया एवं रोलिंग का कार्य नहीं किया गया।

आरोप संख्या-2. इस योजना का प्राक्कलन आपके द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में श्री हरेकृष्ण राम, कनीय अभियंता, प्रखण्ड कार्यालय धनबाद एवं श्री रमेश प्रसाद त्रियार, तत्कालीन सहायक अभियंता एन0आर0ई0पी0 धनबाद के द्वारा तैयार किया गया, जिसकी तकनीकी स्वीकृति श्री सोहन सेठ, कार्यपालक अभियंता, ग्रा0वि0वि0प्र0 धनबाद के द्वारा प्रदत्त की गई है।

आरोप संख्या-3. सड़क निर्माण में स्थल संबंधी स्थानीय स्तर पर जमीन विवादित रहने के बावजूद भी पूर्वी छोर से सड़क का यह कार्य प्रारम्भ किया गया और कार्य अधूरा किया गया।

आरोप संख्या-4. कनीय अभियंता श्री हरेकृष्ण राम द्वारा 25 जनवरी, 2007 को योजना का प्राक्कलन तैयार किया गया तथा सहायक अभियंता श्री रमेश त्रियार के अनुषंसा पर उसी दिन कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 वि0 वि0 प्र0, धनबाद श्री सोहन सेठ के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी।

आरोप संख्या-5. दिनांक 30 जनवरी, 2008 तक योजना में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता योजना कार्य की प्रविष्टि नहीं किया गया परन्तु योजना में आपके द्वारा 58500.00 रु0 भुगतान कर दिया गया जो नियमानुकूल नहीं है।

आरोप संख्या-6. उपरोक्त योजना को स्वीकृत करने के पूर्व न तो आपके द्वारा यह किसी भी तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया जिसके चलते पूर्व निर्मित पक्की सड़क जो जर्जर हो गई थी उसके ऊपर मिट्टी मुरुम सड़क निर्माण का प्रस्ताव दिया गया। स्थल निरीक्षण नहीं कर नरेगा प्रावधान के विपरित पूर्व निर्मित सड़क पर मिट्टी मुरुम सड़क निर्माण की योजना ले लेना एवं सरकारी राशि का दुरुपयोग करना गलत मंशा की पुष्टि होती है।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-3362, दिनांक-18 अप्रैल, 2013 द्वारा आरोपी पदाधिकारी श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह के पत्रांक- 129/भू0आ0, दिनांक-18 मई, 2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक-5136, दिनांक 14 जून, 2013 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-49/गो0, दिनांक-06 जनवरी, 2015 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य दिया गया कि उपलब्ध कागजात से योजना के चयन, कार्यान्वयन एवं भुगतान में आरोपित पदाधिकारी की लापरवाही सुस्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है तथा बचाव में दिये गये तर्क स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। प्रपत्र-'क' में गठित आरोप, आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण उपायुक्त, धनबाद से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-2484, दिनांक-18 मार्च, 2015 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय संकल्प सं0-3928, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा श्री सिन्हा के स्थान पर श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री झा के पत्रांक-184/2015, दिनांक-14 जुलाई, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच-प्रतिवेदन में दिये गये तथ्य आरोपवार निम्नवत् हैं:-

आरोप सं0-01. दोनों पक्षों की सुनवाई से स्पष्ट होता है कि धनबाद प्रखंड के 30 खरीकाबाद पंचायत में BCCL द्वारा पूर्व में निर्मित पक्की सड़क की स्थिति जर्जर हो गयी थी। यह क्षेत्र नगर निगम तथा BCCL क्षेत्र में होने के कारण मनरेगा के दिशानिर्देश के अनुरूप योजनाओं का कार्यान्वयन संभव नहीं था। अतः उप विकास आयुक्त, धनबाद से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर BCCL द्वारा पूर्व निर्मित पक्की सड़क पर मेटल मोरम बिछाने की योजना 1500 फीट लंबाई में प्रारंभ कराया गया जिसमें से प्रथम अग्रिम 7500.00 रुपये दिनांक 25 जुलाई, 07 को भुगतान किया गया तथा द्वितीय अग्रिम 50,000.00 रुपये कनीय अभियंता की अनुशंसा पर 03 अक्टूबर, 07 को भुगतान किया गया। आरोपित पदाधिकारी प्र.वि.पदा. धनबाद का प्रभार सौंप कर कार्य.दंडा. रामगढ के पद पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 से कार्यरत हो गए। इस योजना की जांच निदेशक, DRDA, धनबाद के द्वारा 31 जनवरी, 08 को की गयी। इस जांच प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना में मात्र 250 फीट लंबाई में ग्रेड-I तथा II का कार्य किया गया है जिसके ऊपर मोरम बिछाकर छोड़ दिया गया तथा Roller कार्य नहीं किया गया था। अतः स्पष्ट है कि योजना की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त थी तथा आरोपित पदाधिकारी 31 अक्टूबर, 07 को प्र.वि.पदा. धनबाद के पद से विरमित हो गए थे। प्रतिस्थानी प्र.वि.पदा. को इस योजना का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था। अतः इस योजना का कार्यान्वयन अधूरा छोड़ने के संबंध में गठित आरोप इनके विरुद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

आरोप सं0-2. मनरेगा योजना सं. 01/07-08 का योजना अभिलेख 18 जनवरी, 2007 को प्रारंभ किया गया है। 2006-07 का वार्षिक कार्य योजना में इस योजना के सम्मिलित रहने के आधार पर योजना का स्थल जांच करते हुए प्राक्कलन तैयार करने हेतु आरोपी पदाधिकारी के द्वारा श्री हरिकृष्ण राम, कनीय अभियंता को निदेश दिया गया।

2,94,865.00 रुपये का प्राक्कलन 25 जनवरी, 2007 को कनीय अभियंता के द्वारा तैयार किया गया है तथा इसकी तकनीकी स्वीकृति उसी दिन सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के द्वारा दी गयी है। अतः इस कंडिका में वर्णित तथ्य प्रमाणित होता है।

आरोप सं0-3. योजना स्थल पर जमीन विवादित रहने के बावजूद पूर्वी छोड़ से सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं इस कार्य को अधूरा छोड़ने का आरोप है। BCCL के द्वारा पूर्व निर्मित यह सड़क जर्जर अवस्था में थी इसलिए इस योजना में जो भाग ज्यादा क्षतिग्रस्त था उस भाग में पहले कार्य प्रारंभ किया गया। योजना प्रारंभ होने के लगभग 03 माह बाद आरोपित पदाधिकारी स्थानांतरित होकर रामगढ़ जिला चले गए। यद्यपि इस योजना को पूरा कराने की जिम्मेवारी आरोपित पदाधिकारी के साथ-साथ प्रतिस्थानी प्र.वि.पदा. की थी। परंतु यह योजना 31 जनवरी, 2008 तक अधूरी रह गयी। अतः योजना कार्य अधूरा रखने के लिए आरोपित पदाधिकारी के साथ-साथ प्रतिस्थानी प्र.वि.पदा., धनबाद दोषी हैं। अतः यह आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

आरोप सं0-4. योजना का प्राक्कलन श्री हरिकृष्ण राम, कनीय अभियंता के द्वारा 25 जनवरी, 2007 को तैयार की गयी है जिस पर तकनीकी स्वीकृति श्री रमेश प्रसाद त्रियार, सहायक अभियंता एवं श्री सोहन सेठ, कार्य. अभियंता के द्वारा उसी दिन दी गयी है। यह तथ्य आरोप पत्र के साथ संलग्न प्राक्कलन की छाया प्रति से प्रमाणित होता है परंतु योजना के प्राक्कलन तैयार करने के दिन ही तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के द्वारा देने के लिए आरोपित पदाधिकारी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। अतः यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप सं0-5. इस योजना के मापी के लिए मापी पुस्त प्र.वि.पदा., धनबाद के कार्यालय से निर्गत की गयी थी। दिनांक 31 जनवरी, 2008 को निदेशक, DRDA के जांच के दौरान यह पाया गया है कि मापी पुस्त में दर्ज मापी शून्य है। इसके बावजूद योजना अभिकर्ता को 58,500.00 रुपये का अग्रिम भुगतान करने का आरोप है। योजना के कार्यान्वयन हेतु लाभुक समिति के अध्यक्ष को एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से आरोपित

पदाधिकारी के द्वारा 7500.00 रुपये का प्रथम अग्रिम भुगतान किया गया है। साथ ही योजना अभिकर्ता को 1000.00 रुपये का मेडिसीन किट भी उपब्ध कराया गया है। पुनः 01 अक्टूबर, 2007 को योजना अभिकर्ता के आवेदन पर कनीय अभियंता के द्वारा यह अनुशंसा की गयी है कि योजना में ग्रेड-I एवं ग्रेड- II "कार्य करने के लिए ठवग ब्नजजपदह प्रगति पर है।' अतएव सामग्री क्रय करने के लिए 50,000.00 रुपये अग्रिम दिया जा सकता है। उक्त अनुशंसा के आधार पर आरोपित पदाधिकारी ने दिनांक 03 अक्टूबर, 2007 को 50,000.00 रुपये का द्वितीय अग्रिम भुगतान किया है। जबकि द्वितीय अग्रिम भुगतान के पूर्व कराए गए कार्य की प्रविष्टि मापी पुस्त में दर्ज नहीं थी। योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित दिशानिर्देश तथा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार योजना अभिकर्ता के द्वारा प्रथम अग्रिम से कराए गए कार्य की मापी मापीपुस्त में दर्ज होने के उपरांत ही द्वितीय अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रक्रिया का अनुपालन आरोपित पदाधिकारी के द्वारा द्वितीय अग्रिम भुगतान करने में नहीं किया गया है। योजना की मापी पुस्त में 31 जनवरी, 2008 तक मापी शून्य पायी गयी है। अतः योजना कार्यान्वयन हेतु द्वितीय अग्रिम भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं करने का आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप सं0-6. योजना अभिलेख से स्पष्ट होता है कि 18 जनवरी, 2007 को कनीय अभियंता को योजना का स्थल निरीक्षण कर प्राक्कलन तैयार करने का निदेश दिया गया था। प्राक्कलन के साथ योजना साईट प्लान/इंडेक्स प्लान, विगत 05 वर्षों में किए कार्य की विवरणी तथा जमीन संबंधित विवरण का उल्लेख करने को कहा गया था। परंतु योजना अभिलेख के साथ संलग्न प्राक्कलन में स्थल निरीक्षण का उल्लेख नहीं है। प्राक्कलन के साथ साईट प्लान/इंडेक्स प्लान/विगत पांच वर्षों में किए गए कार्य की विवरणी तथा जमीन की विवरणी का उल्लेख नहीं है। प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति 25 जनवरी, 2007 को सहायक अभियंता तथा कार्य0 अभियंता के द्वारा दी गयी है। तकनीकी स्वीकृति देते समय सहायक अभियंता/कार्य0अभि0 ने भी स्थल निरीक्षण नहीं किया है। प्र.वि.पदा. धनबाद के द्वारा तकनीकी स्वीकृति के आधार पर योजना की

प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उप विकास आयुक्त, धनबाद को 29 जनवरी, 2007 को भेजा गया है। इसमें भी स्थल निरीक्षण का उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि योजना की स्वीकृति बगैर तकनीकी पदाधिकारी के स्थल निरीक्षण के अथवा बगैर आरोपित पदाधिकारी के स्थल निरीक्षण के दी गयी है। संपूर्ण धनबाद प्रखंड के नगर निगम क्षेत्र में रहने के कारण मनरेगा के दिशानिर्देश के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन संभव नहीं था। इस तथ्य से उपायुक्त, धनबाद के द्वारा राज्य सरकार को अवगत कराया गया था।

आरोपित पदाधिकारी ने योजना प्रारंभ करने के पूर्व अपने पत्रांक 1392 दिनांक 30 जुलाई, 2007 के द्वारा BCCL से अनापति प्रमाण पत्र की मांग की गयी थी। धनबाद प्रखंड में मनरेगा की अन्य योजना नहीं ली जा सकती थी अन्य योजना का कार्यान्वयन संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में BCCL द्वारा पूर्व में निर्मित पक्की सड़क जो जर्जर अवस्था में थी के उपर मेटल मोरम गेड-I एवं गेड-II का पथ निर्माण की योजना का कार्यान्वयन आरोपित पदाधिकारी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। दिनांक 31 जनवरी, 2008 को इस योजना की निदेशक, DRDA, धनबाद द्वारा किए गए जांच के दौरान कार्य बंद पाया गया था। बाद में योजना अभिकर्ता के द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त संपूर्ण राशि 58,500.00 (अनठावन हजार पांच सौ रुपये) प्रखंड नजारत में जमा करा दिया गया है। अतः सरकारी राशि के दुरुपयोग करने के उद्देश्य से योजना की स्वीकृति देने एवं कार्यान्वयन कराने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

श्री सिंह के विरुद्ध प्राप्त आरोप, इनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि नरेगा अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़क के लिए लाभुक समिति के माध्यम से योजना कार्यान्वयन के लिए प्रथम अग्रिम 7,500/- रुपये पुनः कनीय अभियंता की अनुशंसा पर बिना मापी के द्वितीय अग्रिम 50,000/- रुपये दिनांक 03 अक्टूबर, 2007 को दिया गया। इस बीच, इनका स्थानांतरण कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ के पद पर हो जाने के कारण आरोपी पदाधिकारी ने दिनांक 03 अक्टूबर, 2007 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनबाद का पदभार त्याग दिया। बाद में दिनांक 31 जनवरी, 2008 को जाँच के क्रम में 230 फीट

लम्बाई में मेटल मोरम बिछाया हुआ परन्तु रोलिंग नहीं किया हुआ पाया गया। आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि प्रथम किस्त 7,500/- रुपये, जो योजना प्रारंभ करने में ही व्यय हो जाती है, जिसके कारण इसकी मापी नहीं हो सकती थी। कनीय अभियंता की अनुशंसा पर द्वितीय अग्रिम 50,000/- कार्यहित में दिया गया। व्यवहारिक रूप से द्वितीय अग्रिम के पश्चात् इनका स्थानांतरण हो जाने के कारण बाद के पदाधिकारी को देखना चाहिए था कि कार्य हुआ है या नहीं। योजना अभिकर्ता द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण राशि प्रखण्ड नजारत में जमा करा दिया गया है। अतः वीरेन्द्र कुमार सिंह को आरोप मुक्त करते हुए मामले को समाप्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 7—50 ।